गृह अपने पास रखेंगे सीएम, गुर्जर को मिलेंगे बड़े विभाग

चंडीगढ़. हरियाणा में नयी सरकार के गठन और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अभी तक विभागों का आवंटन नहीं हो पाया है। नये मंत्रियों में विभागों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस बीच, बृहस्पतिवार को सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने कई केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात की। माना जा रहा है कि सैनी का यह दौरा मंत्रियों के विभाग आवंटन को लेकर ही था। शुक्रवार को सुबह सैनी नयी दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे।

बताते हैं कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी बाहर थे। इस वजह से भी मंत्रियों के विभागों की अलॉटमेंट में देरी हुई। विभागों का आवंटन अब अधिक नहीं लटकेगा। जल्द ही सभी मंत्रियों को विभाग सौंपे जा सकते हैं। नायब कैबिनेट में छह उन मंत्रियों को शामिल किया है, जो मनोहर कैबिनेट में भी थे। वहीं सात नये चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इस बार राज्य मंत्रियों की संख्या भी अधिक है। प्रदेश में 6 कैबिनेट और सात राज्य मंत्री बनाए हैं। राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया है।

माना जा रहा है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेंगे। इसी तरह वित्त विभाग भी वे खुद ही रख सकते हैं। मनोहर पार्ट-।। में भी वित्त विभाग पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपने पास ही रखा हुआ था। ऐसा इसलिए भी संभव है, क्योंकि मौजूदा सरकार अपना पांचवां और आखिरी बजट फरवरी में ही पेश कर चुकी है। नायब सरकार के मंत्रियों की नजरें अब पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को प्राप्त रहे विभागों पर है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों में विभागों को लेकर मारामारी बची है। दिल्ली तक लॉबिंग हो रही है।

गठबंधन में जजपा के बाद आबकारी एवं कराधान, खाद्य एवं आपूर्ति, उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विकास एवं पंचायत, श्रम, पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें), नागरिक उड्डयन व अग्निशमन सेवाएं जैसे बड़े विभाग थे। सूत्रों का कहना है कि मनोहर कैबिनेट में शामिल जिन मंत्रियों को नायब मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उनके पहले वाले विभाग बने रह सकते हैं। बदलाव अगर हुआ तो कमल गुप्ता के विभाग में हो सकता है। उन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया जा सकता है।

कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर के पास कुछ पुराने विभाग बने रहेंगे। संसदीय कार्य मामले मंत्री भी गुर्जर ही रहेंगे। उन्हें पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें) तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन भी दिया जा सकता है।

राज्य मंत्री सीमा त्रिखा को महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा एक-दो और विभाग दिए जा सकते हैं। इसी तरह स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री महिपाल ढांडा को विकास एवं पंचायत मंत्री बनाया जा सकता है।

निकाय विभाग को लेकर रस्साकसी

मनोहर सरकार में शहरी स्थानीय निकाय विभाग डॉ कमल गुप्ता के पास था। इस विभाग को लेकर नये मंत्रियों में जबरदस्त टकराव चल रहा है। बताते हैं कि कई मंत्री यह विभाग लेने के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं। इनमें थानेसर विधायक व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, असीम गोयल भी शामिल हैं। ऐसे में विभाग कमल गुप्ता के पास भी बना रह सकता है। बताते हैं कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पर भी कई मंत्रियों की नजरें हैं। माना जा रहा है कि असीम गोयल को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बनाया जा सकता है।

कांग्रेस डिप्रेशन की स्थिति में, उम्मीदवार हट रहे पीछे : रणजीत

चंडीगढ़. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में देरी को लेकर कैबिनेट मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डिप्रेशन की स्थिति में आ गई है। 1977 में एक बार ऐसा समय आया था, जब लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कोई भी कांग्रेस की टिकट नहीं लेना चाहता था। अब फिर वही दौर आ चुका है, जब कोई भी कांग्रेस की टिकट नहीं लेना चाह रहा है।

कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करने का जरूर दिखावा कर रही है, लेकिन कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है। बृहस्पतिवार को यहां मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि रायबरेली से कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट ले ली है। राहुल गांधी रायबरेली छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की आज देश में ऐसी हालत हो चुकी है, जो पहले उसकी कभी नहीं हुई थी।

लोकसभा की सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें 80 सीटें हैं। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उससे स्थिति का आकलन किया जा सकता है। रणजीत सिंह ने कहा कि जब चुनावी रण में पार्टी का नेता आगे चलता है तभी सेना यानी कार्यकर्ताओं में जोश आता है, लेकिन कांग्रेस हालात बहुत खराब चल रहे हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, पिछले चुनाव के मुकाबले वोट का ग्राफ भी गिरेगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी और फिर से तीसरी बार सत्ता में आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 और 2019 में गुजरात की सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी और प्रधानमंत्री ने खुद उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ा था। रणजीत चौटाला ने विपक्ष को दो टूक जवाब दिया कि सरकार के बदलाव से विपक्ष को कोई फायदा नहीं होने वाला है।

551 निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे गरीब परिवारों के बच्चे

चंडीगढ़. मुख्यमंत्री समान शिक्षा, राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना के तहत प्रदेशभर में 551 निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों का दाखिला होगा। शिक्षा विभाग की ओर से चिराग योजना को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।

चिराग योजना के तहत दाखिला देने की सहमति देने वाले निजी स्कूलों की सूची को शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक कर दिया है। दाखिले के लिए सहमति देने वाले 551 स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन वर्तमान खंड, जिसमें वह पहले से पढ़ रहे हैं, उसे ही तरजीह दी जाएगी। 31 मार्च तक आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी, पहली अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक दाखिला ड्रा निकाले जाएंगे। ड्रा को लेकर अभिभावकों को सूचित किया जाएगा और अभिभावकों की उपस्थिति में ही ड्रा प्रक्रिया पूरी होगी। 10 अप्रैल तक दाखिला प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही 15 अप्रैल तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भी बच्चों का दाखिले का डेटा दर्शाना अनिवार्य होगा। भिवानी जिला में 56, जींद में 48, हिसार में 45, सिरसा में 43, कुरुक्षेत्र में 42, सोनीपत में 35, कैथल व फतेहाबाद में 31-31, करनाल में 30, पानीपत में 29, अंबाला में 27, चरखी दादरी में 19, झज्जर में 23, नूंह में 14, पलवल में 13, रोहतक व यमुनानगर में 12-12, रेवाड़ी में 11, गुरुग्राम में 10, महेंद्रगढ़ में 9, पंचकूला में 7 तथा फरीदाबाद जिला में 4 स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों के मुफ्त एडमिशन हो सकेंगे।

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है...

चंडीगढ़. पूर्व गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया एक्स पर शायराना पोस्ट डाली है। 9 साल और करीब साढ़े चार महीने तक हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विज अब सरकार में हुए बदलाव के बाद कैबिनेट का हिस्सा नहीं हैं। बृहस्पतिवार को पोस्ट में विज ने लिख ङ्क कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौर-ए-जमां हमारा। माना जा रहा है कि इस शेर के जरिये विज ने भाजपा में अपने विरोधियों पर कटाक्ष किया है।

इस पोस्ट पर एक्टिव लोगों ने टिप्पणी भी शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में विज के समर्थकों व अन्य ने पोस्ट पर रिएक्ट किया है। कई जहां विज को ही सलाह देते नज़र आए तो किसी ने कहा कि विज के साथ गहरी साजिश हुई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने विज को अपने एक्स अकाउंट से 'मोदी का परिवार' हटाने की सलाह दे डाली है। बोल्ड स्टैंड के नेचर वाले विज प्रदेश में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद से ही नाराज़ चल रहे हैं। हालांकि पब्लिक प्लेटफार्म पर वे कह चुके हैं कि उनकी किसी से नाराजगी नहीं है।

12 मार्च को अपने मंत्रिमंडल सहित मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नायब सिंह सैनी को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी दिन शाम को

राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सैनी के साथ मंत्री पद की ओथ लेने वाले विधायकों में अनिल विज का भी नाम शामिल था। विज विधायक दल की बैठक को ही बीच में छोड़कर अंबाला कैंट चले गए थे। इसके बाद वे राजभवन भी नहीं पहुंचे। बताते हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी विज को मनाने की कोशिश की लेकिन वे माने नहीं।

डरे हुए हैं विपक्षी राजनीतिक दल : विज

मीडिया से बातचीत में विज ने कहा कि हरियाणा में लोकसभा की सभी दस सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार चाहे जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी जगह मोदी लड़ रहे हैं। हरियाणा में किसी सीट पर प्रत्याशी को लेकर कोई पेच नहीं फंसा है। हमने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। मोदी ही हमारा उम्मीदवार है। दूसरी पार्टियां तय नहीं कर पा रही हैं कि किसे चुनाव लड़वाया जाए। विरोधी दल डरे हुए हैं, इसलिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो रही।

बृजेंद्र सिंह का इस्तीफा मंजूर, खाली हुई हिसार लोकसभा सीट

चंडीगढ़. हिसार लोकसभा क्षेत्र की सीट भी अब रिक्त हो गई है। यहां से भाजपा सांसद रहे बृजेंद्र सिंह का इस्तीफा लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। उनके इस्तीफे को 12 मार्च से ही मंजूर किया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बृजेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हालांकि उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौ. बीरेंद्र सिंह अभी भाजपा में ही हैं।

भाजपा की ओर से लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश की 10 सीटों में से छह पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। जिन चार संसदीय सीटों पर अभी उम्मीदवार नहीं आए है, उनमें रोहतक, सोनीपत व कुरुक्षेत्र के अलावा हिसार भी शामिल है। हिसार सीट को लेकर भाजपा में पेच फंसा हुआ है। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने 10 मार्च को भाजपा छोड़कर नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी।

कांग्रेस में शामिल होने के बाद 12 मार्च को उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को भेज दिया था। बृजेंद्र सिंह हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी थे। 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उन्होंने आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। उस समय उनके पिता चौ. बीरेंद्र सिंह राज्यसभा सांसद थे और उनकी माता प्रेमलता उचाना कलां से भाजपा विधायक थीं।

सरसों खरीद 26 से, गेहूं खरीद होगी पहली अप्रैल से शुरू

चंडीगढ़. हरियाणा में सरसों की खरीद 26 मार्च से और गेहूं की खरीद पहली अप्रैल से शुरू होगी।

रबी सीजन-2024-25 को लेकर तैयारियां पूरी है। इस सीजन में सरसों के लिए 5650 रुपये, गेहूं के लिए 2275 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया गया है। इस बार भी फसल खरीद का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 फसल सीजन में फसल खरीद के लगभग 90 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में डाले गए।

सरसों की सरकारी खरीद हैफेड व हरियाणा भंडारण निगम द्वारा की जाएगी। सरसों के लिए 106 मंडिया/खरीद केंद्र बनाए हैं। इस बार मंडियों में 14.28 लाख मीट्रिक टन आवक होने की संभावना हैं। 2022-23 में 3.17 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2023-24 में 6.83 लाख मीट्रिक टन आवक हुई।

गेहूं की खरीद के लिए 417 मंडियां/खरीद केंद्र बनाए हैं। इस बार 112.14 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन होने की संभावना हैं।

किसानों को गेहूं की खरीद के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी का सामना न करना पड़े, इसके लिए 7300 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। गेहूं की खरीद के लिए बेल की भी समुचित व्यवस्था की गई है।

पोर्टल पर दर्ज ब्योरे अनुसार होगी खरीद

फसल खरीद मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज डाटा के आधार पर की

जाएगी। इस पोर्टल पर सरसों के लिए 4 लाख 74 हजार 768 किसानों ने 18 लाख 6 हजार 326 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है। साथ ही, गेहूं के लिए 7 लाख 82 हजार 921 किसानों ने 41 लाख 64 हजार 324 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है। रबी सीजन-2024-25 में चना व जौ की भी खरीद पहली अप्रैल से की जाएगी।

सरकार सरसों की खरीद शुरू करे और बकाया मुआवजा दे : हुड्डा

चंडीगढ़. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से जल्द सरसों की खरीद शुरू करने और किसानों को बकाया मुआवजा देने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि मंडियों में फसल की आवक शुरू हो चुकी है। लेकिन सरकार 26 मार्च से खरीद शुरू करने की बात कह रही है। तैयारियों को देखकर यह भी होता संभव नजर नहीं आ रहा। चूंकि एक बार फिर सरकार किसानों को पोर्टल के जंजाल में फंसाना चाहती है।

पूर्व सीएम ने कहा कि 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पार्टल पर 9.25 लाख किसानों ने 61.45 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। इसमें से 10.40 लाख एकड़ रकबे का रिकॉर्ड मिसमैच है। जब तक यह खामी दूर नहीं होती, तब तक सरकार किसानों की फसल नहीं खरीदेगी। यानी सरकार की गलती का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि बिना देरी के सरसों की खरीद शुरू करे। साथ ही, गेहूं की आवक के लिए पहले से ही तमाम तैयारियां को पूरा किया जाए। पूर्व सीएम ने सरकार से किसानों को बकाया मुआवजा देने की मांग भी दोहराई है। अब तक सरकार ने न बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया और न ही पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के नुकसान की भरपाई की है। कई साल से किसान इंतजार में बैठे हैं। जैसे-तैसे भाजपा ने 2022 के खराबे का नाममात्र मुआवजा रिलीज किया है।

रजत कल्सन समेत अनेक लोगों ने ज्वाइन की कांग्रेस

दलित अधिकार कार्यकर्ता अधिवक्ता रजत कल्सन समेत दर्जनभर सामाजिक कार्यकर्ता बृहस्पतिवार को अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। नयी दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौ. उदयभान के नेतृत्व में सभी ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के पार्टी में आने से कांग्रेस और मजबूती के साथ दलित व पिछड़ों की आवाज उठा पाएगी। उन्हें उम्मीद है कि सभी पुरजोर तरीके से वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ेंगे। कल्सन के साथ फतेहाबाद के भीम आर्मी के 6 साल तक अध्यक्ष रहे भूषण नुनिया, अशोक रत्ताखेड़ा व बलविंदर सिंह तथा भाटला संघर्ष समिति के मुख्य सदस्य अजय भाटला, विकास भाटला, राजेश भाटला, रोहतास कुमार ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

नामांकन प्रक्रिया शुरू होने तक बनेंगे वोट

अम्बाला . भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई सी विजल एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना की शिकायत अब आम नागरिक भी इस पर दर्ज करवा सकते हैं। कोई भी पात्र नागरिक नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपनी वोट बनवा सकता है। इस दौरान किसी की वोट काटने का काम नहीं किया जायेगा। जिले में अतिरिक्त उपायुक्त को नोडल अधिकारी लगाया गया है। यह जानकारी आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. शालीन ने अपने कार्यालय में लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक लेते हुए दी। उन्होंने बताया कि सी विजल एप पर शिकायत आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त की गई टीम मौके पर जाकर कार्रवाई करेगी और समस्या का निदान करेगी। सी विजल ऐप पर जो शिकायत प्राप्त होगी, 100 मिनट के अंदर उसका समाधान किया जायेगा। साथ ही ईवीएम मशीन व वीवी पैट से सम्बन्धित विषय पर भी जानकारी दी गई।

चुनाव के दौरान वे पुलिस कर्मचारी या अधिकारी जो यमुनानगर, पंचकूला, अम्बाला से संबध रखते हैं और उनकी तैनाती अम्बाला में है, ईडीएस प्राप्त कर सकते हैं ताकि मतदान के दिन जहां उनकी डयूटी हो, वे भी अपने मत का प्रयोग कर सकें। उन्होंने सभी अधिकारियों को चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुपालना के तहत अपनी डयूटी का निर्वहन करने बारे निर्देश दिए। उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शैडयूल बनाकर प्रशिक्षण दिलवाने को कहा। उन्होंने कहा कि एआरओ व एईआरओ इस कार्य में लीड करें। ईवीएम व वीवीपैट से सम्बन्धित प्रक्रिया की जानकारी दें। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता, एसडीएम दर्शन कुमार, एसडीएम बिजेंद्र सिंह, एसडीएम यश जालुका, एसडीएम सतिंद्र सिवाच, आरटीए सुशील कुमार, चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार, डीएसपी रमेश कुमार, डीडीपीओ दिनेश शर्मा के साथ-साथ नोडल अधिकारी आदि मौजूद रहे।

कंट्रोल रूम भी बनाया गया

चुनाव कार्यालय अम्बाला शहर में कंट्रोल रूम कमरा नंबर 101, 102 स्थापित किया गया है। 1950 भी सैटअप किया गया है जिस पर चुनाव प्रक्रिया की जानकारी ली व दी जा सकती है। इसके अलावा मतदाता अपने मत व बूथ से सम्बन्धित कोई भी जानकारी वोटर हेल्पलाइन नंबर, एप पर अपने पंजीकृत मोबाइल के माध्यम से ले सकता है।

अर्धसैनिक बलों व पुलिस की रहेगी ड्यूटी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. शालीन ने यह भी कहा कि चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्वक तरीके से करवाने बारे भी तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के साथ-साथ गृहरक्षी-होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जायेगी।

संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों की वास्तविकता को जानते हुए वहां पर अलग से पुलिस की तैनाती की जायेगी। रोड शो के दौरान यदि कोई गाड़ी, वाहन बिना परमिशन के पाया गया तो उसे इम्पाउंड भी किया जायेगा।